भारत को निवेश की बूस्टर डोज की आस

कोरोना की तीसरी लहर के बीच भारत को निवेश की बूस्टर डोज मिलने की उम्मीद जगी है। विश्व आर्थिक मंच के दावोस शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन ने विदेशी कंपनियों का ध्यान एक बार फिर भारत की ओर आकर्षित किया है। सम्मेलन में पीएम मोदी ने भी कहा है कि भारत में निवेश का यह बिल्कुल सही मौका है।

कोरोना की शुरुआत में लॉकडाउन लगा तो सब कुछ बंद होने से अर्थव्यवस्था का पहिया भी थम गया। लेकिन, यह रुकावट अधिक समय तक नहीं रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील 'आपदा में अवसर' को भारतीयों ने साकार किया और आज भारत को उस जगह लाकर खड़ा कर दिया कि हर किसी की निगाहें हम पर हैं। देश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर पर कई ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं, जिसने निवेश की राह को आसान बना दिया है। पीएम मोदी ने भी दावोस सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में यह निवेश का सबसे सही समय है। इसके बाद देश में निवेश बढ़ने की आस और अधिक बढ़ गई है।

ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम 25 वर्षों के लक्ष्य को लेकर नीतियां बना रहे हैं और निर्णय ले रहे हैं। हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा दिया है और सरकार के दखल को कम से कम कर रहे हैं। यह निवेश का सबसे सही समय है। भारत जैसे मजबूत लोकतंत्र ने पूरे विश्व को एक खूबसूरत उपहार दिया है और वह उपहार है बुके ऑफ होप। इसमें 21वीं सदी को सशक्त करने वाली तकनीक और हम भारतीयों की प्रतिभा शामिल है।

कॉरपोरेट टैक्स को सरल बनायाः कोई भी विदेशी कंपनी निवेश से पहले कॉरपोरेट टैक्स रेट देखती है। इस दिशा में सरकार ने कदम उठाते हुए कॉरपोरेट टैक्स रेट को सरल बनाया है। इसके अलावा रेट को कम करके दुनिया में प्रतिस्पर्धी बना दिया है। भारत ने सूचना प्रौद्योगिकी और बीपीओ सेक्टर संबंधी पुराने नियमों में सुधार किए हैं। बीते साल में ही 25 हजार से ज्यादा अनुपालनों को कम किया है। इतना ही नहीं 14 सेक्टर में 26 अरब डॉलर की उत्पादन युक्त प्रोत्साहन योजना लागू की है।

तकनीकी क्षेत्र में मजबूती बढ़ीः भारत ने तकनीकी क्षेत्र में भी खुद को मजबूत किया है। सेवा क्षेत्र हो या शिक्षा या फिर स्वास्थ्य सभी जगह तकनीक का इस्तेमाल बढ़ा है। नए निवेश के लिए तकनीक में मजबूत होना बेहद जरूरी है। भारत के पास विश्व का सबसे बड़ा, सुरक्षित और सफल डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म है तथा सिर्फ पिछले महीने में ही यूनीफाइड पेमेन्ट इंटरफेस के जरिए 4.4 अरब का लेन-देन हुआ है। यह भारत की मजबूत स्थिति को बताने के लिए काफी है।

पीई वीसी में निवेश बढ़ाः निजी इक्विटी (पीई) एवं उद्यम पूंजी (वीसी) कोषों ने बीते साल यानी 2021 में भारतीय कंपनियों में 77 अरब डॉलर का निवेश किया, जो इससे एक साल पहले की तुलना में 62 फीसदी अधिक है। 2021 में पीई एवं वीसी कोषों ने 1,266 सौदे किए, जो वर्ष 2020 की तुलना में 37% अधिक है।

03 अरब डॉलर निवेश साल 2021 में भारत को मिला, साथ ही पीई वीसी में निवेश 62 फीसदी बढ़ा

60 हजार से ज्यादा स्टार्ट-अप अब तक देश में रजिस्टर्ड हैं, 2014 में संख्या सिर्फ सैकड़ों थीं।

भारतीय अर्थव्यवस्था और रफ्तार पकड़ेगी

कोरोना महामारी की चलते आई कई तरह की अड़चनों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था अगले 12 माह के दौरान रफ्तार पकड़ेगी। पीडब्ल्यूसी के वार्षिक वैश्विक सीईओ सर्वे में यह बात कही गई है। इस सर्वे में भारत से 77 सीईओ शामिल हुए। 99 फीसदी भारतीय सीईओ का मानना है कि अगले 12 महीनों में आर्थिक वृद्धि दर में सुधार होगा। 94 फीसदी भारतीय मुख्य कार्यकारी मानते हैं कि अगले एक साल में वैश्विक वृद्धि दर भी सुधरेगी।

इन मोर्चों पर दमखम साबित किया

1 कोरोना के दौरान भारत के आईटी सेक्टर ने 24 घंटे काम कर तमाम देशों को मुश्किलों से बचाया है। आज भारत दुनियाभर में रिकॉर्ड इंजीनियरों को भेज रहा है। भारत में ही 50 लाख से अधिक सॉफ्टवेयर डेवलेपर्स काम कर रहे हैं

2 भारत में दुनिया में तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा 80 यूनिकॉर्न्स हैं। 2014 में कुछ सौ स्टार्टअप रजिस्टर्ड थे। आज 60 हजार पार हैं। 40 हजार तो 2021 में बने हैं। हर साल 16 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय स्टार्ट-अप डे मनाया जाएगा।

3 कोरोना के समय में भारत ने 'वन अर्थ,वन हेल्थ' के विजन पर काम किया। कई देशों को जरूरी दवाइयां, वैक्सीन देकर करोड़ों लोगों की जान बचाई। इतना ही नहीं आज भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा फार्मा उत्पादक है।

4 कोरोना के दौरान श्रमिक वर्ग एवं गरीब परिवारों को रोजी-रोटी की चिंता थी। उस समय भारत ने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त खाद्यान्न उपलब्ध कराया है, जो कि आज भी जारी है। अहम है कि शायद दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य कार्यक्रम है।

भारतीय उद्योग जगत का भी साथ

देश में निवेश के अवसरों पर उद्योग जगत भी सहमत है। उद्योग मंडल फिक्की ने कहा कि सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता से वैश्विक निवेशकों के बीच भारत का आकर्षण और बढ़ेगा। वहीं, वेदांता समूह के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने भारत को कारोबारी सुगमता की राह पर अग्रसर बताते हुए कहा कि सरकार राजस्व के बजाय उत्पादन बढ़ाने पर जोर दे रही है। भरोसा, प्रतिभा एवं उद्योगिक विकास के आधार स्तंभ हैं।